शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 02 – 09 जून 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या सी.बी.आई. हरिकेश मीणा और देशराज की जमानते रद्द करवा पायेगी?

शिमला/शैल। क्या सी.बी.आई. देशराज और हरिकेश मीणा की जमानते रद्द करवा पायेगी? क्या सी.बी.आई. भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमाणित कर पायेगी? क्या ओंकार शर्मा और डॉ. अतुल वर्मा संजीव गांधी की एल.पी.ए. में जवाब दायर करेंगे? क्या विमल नेगी प्रकरण सुक्खू सरकार और कांग्रेस की सेहत पर प्रभाव डालेंगे? यह सारे सवाल संजीव गांधी की एल.पी.ए. पर सरकार और अन्य को नोटिस जारी होने के बाद चर्चा में आये हैं। क्योंकि संजीव गांधी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को एल.पी.ए. में इसी कारण से चुनौती दी है कि क्योंकि एकल पीठ में जो स्टेटस रिपोर्ट डी.जी.पी. ने दायर की है उसमें संजीव गांधी के बतौर एस.आई.टी. नियन्ता आचरण को लेकर कुछ प्रतिकूल टिप्पाणीयां है जिनका जवाब देने के लिये उन्हें समय नहीं मिला था। इसी तरह ओंकार शर्मा की प्रशासनिक जांच रिपोर्ट को लेकर सरकार को कुछ एतराज रहे हैं। इसीलिये एकल पीठ के फैसले के बाद सरकार ने ओंकार शर्मा, डी.जी.पी. अतुल वर्मा और संजीव गांधी को छुटी पर भेज दिया था। यह तय है कि सरकार ने इन लोगों को छुटी पर भेजने का फैसला किसी ठोस आधार पर ही लिया होगा। इसलिये एल.पी.ए. की सुनवाई में मान्य अदालत ने इन अधिकारियों को अपना जवाब दायर कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। स्व. विमल नेगी की मौत प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसी आधार पर सी.बी.आई. को सौंपने का फैसला लिया था क्योंकि इसमें डी.जी.पी. और संजीव गांधी की स्टेटस रिपोर्टो में अन्त: विरोध थे और ऐसे अन्त: विरोधों के चलते इन निष्कर्षो पर अविश्वास उठना स्वभाविक ही था।

स्मरणीय है कि स्व. विमल नेगी की मौत के प्रकरण से उनके परिजनों ने पावर कारपोरेशन के शीर्ष अधिकारियों पर नेगी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाये हैं। इस प्रताड़ना का कारण यह बताया गया है कि स्व. नेगी पर इन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में सहभागिता और इसमें किसी भी तरह का अवरोध न डालने का दबाव रहा है। भ्रष्टाचार के इस आरोप का संकेत इंजीनियर ग्रोवर ने भी प्रशासनिक जांच में ओंकार शर्मा को सौंपे शपथ पत्र में दिया है। पावर कारपोरेशन में भ्रष्टाचार के आरोप लंबे अरसे से लगते आ रहे हैं। इन आरोपों को लेकर एक समय एक पत्र बम भी चर्चा में रह चुका है और उसमें लगे आरोपों को नजरअन्दाज कर दिया गया था। यह सामान्य समझ की बात है कि जिस संस्थान में सैकड़ो करोड़ की परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा था वहां पर कर्मचारियों/अधिकारियों में कार्य संस्कृति को लेकर उभरे मतभेदों के मूल में भ्रष्टाचार का होना स्वभाविक है। क्योंकि कार्यस्थल पर आपसी मतभेदों का कारण पारिवारिक संबंध नहीं होते। स्व.नेगी के परिजनों और पावर इंजीनियर एसोसियेशन ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। फिर जब स्व. नेगी का शव बरामद होता है तब उस समय उनके मोबाइल और पेन ड्राइव को गायब कर देना और उसे फारमैट करना वह भी उस व्यक्ति द्वारा जो किसी एस.आई.टी. का सदस्य ही नहीं था। उस कर्मचारी पंकज ने यह सब क्यों किया, किसके ईशारे पर किया यह अभी तक बाहर नहीं आया है। डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट में इस पंकज के व्यवहार पर टिप्पणी है लेकिन शायद एस.आई.टी. की स्टेटस रिपोर्ट में नहीं है।

इस प्रकरण में परिजनों और पावर इंजीनियर एसोसियेशन और प्रशासनिक जांच में जितने भी लोगों के ब्यान कमलबद्ध किये गये हैं सबने प्रताड़ना की पुष्टि की है। इस प्रताडना के मुख्य आरोप देशराज और हरिकेश मीणा पर लगे हैं और यह दोनों अग्रिम जमानत पर हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या सी.बी.आई. इन अधिकारियों की जमानत रद्द करवा कर इन से गहन पूछताछ कर पायेगी? इसी तरह संजीव गांधी ने जो एतराज डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट पर लगाये हैं यहां तक कह दिया है कि कुछ पूर्व मामलों मिडल बाजार के रसोई ब्लास्ट और फिर रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मो समाज मामले में डी.जी.पी. और मुख्य सचिव की भूमिकाएं संदिग्ध रही हैं। यह आरोप अब आम चर्चा में आ गये हैं क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी लगा रहा है। इन आरोपों के बाहर आने पर सरकार पर भी यह सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि सरकार इन आरोपों पर अब तक चुप क्यों रही है। इस प्रकरण में अब सबकी नजरें इस पर लगी है क्या सी.बी.आई. देशराज और मीणा की अग्रिम जमानते रद्द करवा कर भ्रष्टाचार के आरोपों की सत्यता आम आदमी के सामने ला पायेगी? इसी के साथ यदि ओंकार शर्मा के छुटी पर और डी.जी.पी. अतुल वर्मा के सेवानिवृत हो चुकने के बाद क्या इन पदों पर तैनात नये अधिकारी उच्च न्यायालय में जवाब दायर करते हैं या नहीं। जवाब दायर न करने की स्थिति में माना जा रहा है कि संजीव गांधी को इस मामले में सीमित राहत का मार्ग स्वत: ही प्रशस्त हो जाता है।

चेतन ब्रागटा का भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस सरकार पर संरक्षण का आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एक और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है और इस भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस सरकार का संरक्षण झलक रहा है, यह आरोप भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्रागटा ने सरकार पर लगाये।

चेतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है। सोलन जिला के नालागढ़ पुलिस चौकी में यह मामला आता। इस भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी अधिकार भी संलिप्त है और जल्द ही उनका नाम इस मामले से जुड़ सकता है और सरकारी अधिकारी तभी संरक्षण देते हैं जब सरकार का संरक्षण स्वयं होता है।

उन्होंने कहा कि नालागढ़ की प्रिंटिंग प्रेस में 1200 पर्चियां छापी गई। इन पर्चियों के माध्यम से शूलिनी मेले के आयोजन के लिए दुकानदारों और आम लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाना था। मगर सोलन जिला के नालागढ़ में एक डिपो संचालक ने प्रिंटिंग प्रेस में जाकर फर्जी पर्चियां छपवा डाली। डिपो संचालक को खाद्य पूर्ति विभाग का निरीक्षक ने एक ऑरिजनल पर्ची दी थी। इसके आधार पर 1200 फर्जी पर्चियां छापी गई। इसमें स्कैनर और डीसी सोलन की ईमेल – आईडी भी प्रकाशित है। उन्होंने बताया की पर्ची में प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी नहीं लिखा था। इसलिए उसकी भूमिका भी संदेह में है। फूड इन्सपैक्टर ने डिपो संचालक को एक ऑरिजनल स्पिल मुहैया कराई थी। फूड इन्सपैक्टर की भूमिका की जांच की जा रही है। मां शूलिनी के नाम से होता है मेले का आयोजन बता दें कि सोलन जिला के लोगों की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के नाम से सोलन में हर साल मेला लगता है।

उन्होंने कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से फैला है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार के मामलों में कई सरकारी अधिकारियों ने अपनी जान भी गवा दी है।

भाजपा हिमाचल प्रदेश मांग करतीं है कि पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को करता सम्मिलित पाया गया है उस पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों पर भी एक्शन लेने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, पूरी जांच में तथ्यों को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

राज्यपाल ने हिमाचल के विशेष ओलंपिक्स खिलाड़ियों को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विशेष ओलंपिक खिलाड़ियों के योगदान को सराहने और उन्हें भरपूर सहयोग देने पर बल दिया है ताकि इनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। स्पेशल ओलंपिक्स भारत – हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित

सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज और सरकार दोनों को विशेष खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने और उनका उत्साहवर्द्धन करने के लिए आगे आना चाहिए।

इस समारोह का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स – 2023 और ईटली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड विंटर गेम्स – 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित किया गया। ईटली के टयूरिन में आयोजित प्रतियोगिता में 49 सदस्यों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया जिनमें 30 खिलाड़ी और 19 सहायक स्टाफ शामिल था। इनमें से 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे।

राज्यपाल ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि दृढ़संकल्प, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना सम्भव है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल देश व प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी दिया है। उन्होंने इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों की विशेष तौर पर सराहना की, जिनके संयम, सर्मपण और विश्वास ने उन्हें विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया।

शुक्ल ने कहा कि भारत ने इन खेलों में 33 पदक जीते जो इस बात का प्रमाण है कि जब प्रतिभा को अवसर प्रदान किया जाए तो असम्भव भी सम्भव बन जाता है। हिमाचल प्रदेश से 15 खिलाड़ियों और 8 प्रशिक्षकों को तैयार करने तथा इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों के लिए एनएचपीसी स्पोर्ट्सेंटर के योगदान को सराहते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संस्थान खेल संस्कृति को व्यापक प्रोत्साहन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स भारत और एशिया पेसिफिक एडवाइज़री काउंसिल की अध्यक्षा डॉ. मलिका नड्डा के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने वर्ष 2002 में बिलासपुर से विशेष ओलंपिक्स की पहल की। उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश की 23 वर्ष की सफल यात्रा पूरी करने और शिमला व नारकण्डा में वर्ष 2008 में पहले नेशनल विंटर गेम्स को सफलतापूर्वक आयोजित करने पर नड्डा को बधाई दी।

राज्यपाल ने विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया।

डॉ. मलिका नड्डा ने कहा कि भारत की लगभग पांच प्रतिशत जनसंख्या विशेष रूप से सक्षम है, जिनमें से लगभग एक प्रतिशत लोग बौद्धिक विकलांगता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि टयूरिन की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में 15 हिमाचल प्रदेश से हैं।

उन्होंने बताया कि विशेष बच्चों के प्रशिक्षण के लिए एनएचपीसी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में नौ खेल केंद्र विकसित किए गए हैं जबकि देश में ऐसे 72 केंद्र कार्यशील हैं। उन्होंने पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली धनराशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

स्पेशल ओलंपिक्स भारत – हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक परिक्षित महदूदिया ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और चम्बा में अनुकरणीय कार्य के लिए वन समितियों को किया सम्मानित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा में केएफडब्ल्यू परियोजना के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाली जिला कांगड़ा व चंबा की ग्राम वन प्रबंधन समितियों विलेज फोरेस्ट मैनेजमेंट सोसायटी को सम्मानित

किया। उन्होंने राज्य स्तर पर वर्ष 2021 – 22 के लिए प्रथम पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति लगडू को एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार डलहौजी वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति छम्बर को 60 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति भटेड़ को 40 हजार रुपये प्रदान किये। वर्ष 2022 – 23 के लिए राज्य स्तर का एक लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति भटेड़, 60 हजार रुपये का दूसरा पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति जैनी मसरूर – 2 तथा तीसरा पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति लगडू को 40 हजार रुपये प्रदान किया। वर्ष 2023 – 24 के लिए राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति जैनी मसरूर – 2, द्वितीय पुरस्कार 60 हजार रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति भटेड़ तथा तृतीय पुरस्कार 40 हजार रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति लगडू को प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 – 22 का देहरा वन मंडल स्तर का 50 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार खुडियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति, लगडू, 30 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार नगरोटा सूरियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति, भटेड़ तथा 20 हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार देहरा वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति नौशेरा को प्रदान किया जबकि वर्ष 2022 – 23 का देहरा वन मंडल स्तर का 50 हजार रुपये का पहला पुरस्कार नगरोटा सूरियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति भटेड़, 30 हजार रुपये का दूसरा पुरस्कार नगरोटा सूरियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति जैनी मसरूर – 2 और 20 हजार रुपये का तीसरा पुरस्कार नगरोटा सूरियां की ग्राम वन प्रबन्धन समिति बलडोआ ने प्राप्त किया।

वर्ष 2023 – 24 का देहरा वन मंडल स्तर का 50 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार नगरोटा सूरियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति जैनी मसरूर – 2, 30 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार नगरोटा सूरियां की ग्राम वन प्रबन्धन समिति, बलडोआ तथा 20 हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार नगरोटा सूरियां वन रेंज की ग्राम वन प्रबन्धन समिति लगडू को 40 हजार रुपये प्रदान किया। वर्ष 2023 – 24 के लिए राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति जैनी मसरूर – 2, द्वितीय पुरस्कार 60 हजार रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति भटेड़ तथा तृतीय पुरस्कार 40 हजार रुपये देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबन्धन समिति लगडू को प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने एवं निगरानी का काम किया। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण न केवल जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारी नदियों के उद्गम, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीविका उपार्जन से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र लगभग 15,443 वर्ग किलोमीटर आंका गया है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 28 प्रतिशत है और प्रदेश का वर्गीकृत वन क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत है। यह क्षेत्र हरित आवरण से परिपूर्ण है और यह हमें एक अनूठी पहचान और जिम्मेदारी प्रदान करता है। यहां के लोग प्रकृति के साथ आध्यात्मिक और पारंपरिक संबंध रखते हैं। बढ़ती आबादी, विकास कार्यों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण हमारे वन संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से सतत् और वैज्ञानिक पद्धति से वन प्रबंधन की रणनीतियां अपनाई हैं।

उन्होंने कहा कि जिन समितियों ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 22.5 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में दिए जायेंगे, इसमें से 2.5 करोड़ रुपये वित्तरित किए जा चुके हैं तथा शेष राशि इसी वर्ष उनके खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रकृति और वनों के संरक्षण के इस अभियान में आगे आने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि सभी विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, समृद्ध और हरा – भरा हिमाचल मिल सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत दोनों जिलों में 13,300 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व भूमि बचाव का कार्य किया गया है। कांगड़ा व चंबा जिला में 8300 हेक्टेयर भूमि पर 61 हज़ार पौधे लगाए गए हैं जबकि शेष भूमि से लैंटाना हटाई गई है तथा यह परियोजना 30 मार्च, 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

हिमाचल प्रदेश में भूकंप तैयारियों पर 9वां राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश भर में 9वां राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास आयोजित किया। यह मॉक अभ्यास घटना प्रतिक्रिया प्रणाली आईआरएस के राष्ट्रीय दिशा – निर्देशों के अनुसार किया गया, जिसे राज्य आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 सितंबर 2017 को औपचारिक रूप से अधिसूचित इंसिडेंट रिस्पांस टीमें गठित करने के बाद से अपनाया गया है।

इस मेगा मॉक अभ्यास को तीन प्रमुख चरणों में आयोजित किया गया। 27 मई 2025 को ओरिएंटेशन और कोऑडिनेशन कार्यशाला, 3 जून 2025 को टेबल – टॉप अभ्यास तथा 6 जून 2025 को वास्तविक तौर मैगा मॉक अभ्यास का आयोजन शामिल है। इस अभ्यास में राज्य के सभी जिलों में कुल 109 सिमुलेशन साइट्स पर गतिविधियां आयोजित की गई। जिनमें बिलासपुर में 4, चंबा में 9, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 17, किन्नौर में 7, कुल्लू में 7, लाहौल – स्पीति में 9, मंडी में 12, शिमला में 12, सिरमौर में 7, सोलन में 9 तथा ऊना जिला में 6 साईट्स शामिल हैं।

मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न भूकंप – जनित आपदा परिदृश्यों जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड गलोफ, भूस्खलन, चट्टानों का गिरना, बांध टूटना, इमारतों का ढहना, अस्पतालों की आपातकालीन प्रतिक्रिया, अग्निकांड, औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव और बड़े हादसों की संभावनाओं वाले इकाइयों एमएएच पर आधारित स्थितियों का अभ्यास किया गया।

इस अभ्यास में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीएमए, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारत – तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, दीपक प्रोजेक्ट और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राज्य स्तर पर होमगार्ड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीएमए, अग्निशमन सेवा, पुलिस और अन्य विभागों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सफल समन्वय में अभ्यास को अंजाम दिया।

अभ्यास के उपरांत हुई डी – ब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व – आपदा प्रबंधन के.के. पंत ने की। उन्होंने कहा कि हम जितना अधिक शांति में पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे अभ्यास के दौरान पाई गई कमियों को दूर करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलों में नियुक्त प्रेक्षकों ने अपने विस्तृत सुझाव दिए और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की। सभी जिलों के उपायुक्तों, जो कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के अध्यक्ष भी हैं, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अभ्यास के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन डी.सी. राणा, ने सभी जिलों से अनुरोध किया कि वे चिकित्सा प्रतिक्रिया योजना, लॉजिस्टिक तैयारियों और राहत एवं बचाव तंत्र को और अधिक मजबूत करें। उन्होंने वीसैट कम्युनिकेशन नेटवर्क की स्थापना और प्रभावित क्षेत्रों के भू – स्थानिक मानचित्रण हेतु जीआईएस प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुधीर बहल ने सभी प्रतिक्रिया एजेंसियों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सम्बद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एकीकृत प्रयासों और प्रभावी अंतर – विभागीय समन्वय से ही आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों से सतर्क, सक्रिय और हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने का आहवान किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अध्यापकों के स्थानांतरण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

शिमला/शैल। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर 5 जून, 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसला लिया है। यह निर्णय वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025 – 26 की समाप्ति तक जारी रहेगा।

प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री शिप्की – ला गांव से करेंगे 'सीमा पर्यटन' की शुरूआत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू सीमावर्ती शिप्की – ला गांव से 'सीमा पर्यटन' पहल की शुरूआत करने जा रहे है जिससे देश भर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल – स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुन्दरता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अपने आगामी दो दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान इस पहल का शुभारम्भ करेंगे।

यह 'सीमा पर्यटन' पहल राज्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जो पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, शिप्की – ला ग्यू मठ, खाना दुमटी, सांगला, रानी कंडा, छितकुल तथा लाहौल – स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी तथा वहां रह रहे लोगों की सांस्कृतिक और रहन – सहन की तरीके से अवगत करवाएगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को उठाया है। यह एक दीर्घकालिक प्रयास था जो अब सकारात्मक परिणाम देने जा रहा है और इन दूर – दराज जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ – साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र की अनूठी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना भी शामिल हैं। भारत चीन की सीमा से सटे इन क्षेत्रों में विशेष अनुमति लेकर जाना पड़ता था लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल बना दी गई है। नए दिशा – निर्देशों के अनुसार स्थानीय निवासी और प्रमाणित पर्यटक अब वैद्य पहचान पत्र दिखाकर इन स्थानों पर जा सकते हैं। आईटीबीपी और सेना निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी।

यह पहल स्थानीय अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पर्यटन के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाने और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए सार्थक सिद्ध होगी।

यह कदम राज्य के विकास में एक परिवर्तनकारी निर्णय है जो सुरक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन का समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार भारत के सबसे दूरस्थ गांव को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किए बगैर मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाज़ार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एचपीकेवीएन की 16वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के उन्होंने युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के

अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास के महत्त्व पर बल दिया।

उन्होंने निगम को बाजारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता और रोजगार योग्यता बढ़ाना सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के वाकनाघाट में उत्कृष्टता केंद्र तथा काजा और उदयपुर में म डल कैरियर केंद्रों के अलावा नालागढ़ में ग्रामीण आजीविका केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि युवाओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सकें।

बोर्ड ने आरएलसी सराज, मॉडल कैरियर केंद्रों मंडी और बद्दी के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यय को भी मंजूरी दी।

सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 से अब तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं से 45,455 युवाओं को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 39,794 युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण – पत्र दिए जा चुके हैं तथा 8,586 प्रशिक्षुओं को रोज़गार मिल चुका है।

प्रदेश में शिक्षकों के भरे गए 6 हजार से अधिक पद:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय स्कूलों में विभिन्न शिक्षकों के 6 हजार से अधिक पद भरे जा चुके हैं तथा निकट भविष्य में राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3100 और पद भरे जायेंगे, जिसकी चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह जानकारी उन्होंने अभिलाषी विश्वविद्यालय चैलचौक के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में दी। इस मौके पर रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विपरीत वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 8950 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में काफी समय से रिक्त चल रहे 119 प्रधानाचार्यो के पदों को भरा गया है। इसके अलावा सहायक प्रोफेसर के 484 पद भी भरे गए हैं।

इससे पूर्व रोहित ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय बासा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनैड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने महाविद्यालय तथा

स्कूल में अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिलाषी विश्वविद्यालय का अहम् योगदान है और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित कर प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। संस्थान द्वारा कम अवधि में ही आधुनिक नवाचार – युक्त और रोजगारोन्मुखी पाठयक्रमों वाले विश्वविद्यालय के रूप में एक नई मिसाल कायम की है। वर्तमान में देशभर के छात्र यहां अध्ययन के लिए आ रहे हैं तथा नई संभावनाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे नवोन्मेषी और जॉब ओरिएंटेड पाठयक्रम न केवल युवाओं के भविष्य को संवार रहें हैं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास में भी योगदान दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डा.आर.के. अभिलाषी ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पटे के मालिकाना हक प्रमाण – पत्र वितरित किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 48.48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

रिकांगपिओ में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29.88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का शिलान्यास तथा 10.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ हॉस्टल, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं। उन्होंने आईस स्केटिंग रिंक कल्पा में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पटे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पटे दिए गए हैं। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पटे वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिप्की – ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिप्की – ला जा सकते हैं। इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी को बल मिलेगा तो वहीं पर्यटक भी यहां पहुंच सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

मुख्य मंत्री ने किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से सबद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने खेल परिसर और इंडोर स्टेडियम के लिए 10 – 10 करोड़ रुपये, देने की घोषणा की।

उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने को खेलो क्रिकेट टुक्पा क्वीन टीम के 11 सदस्यों को 10 – 10 हजार देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला रखने के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला।

इससे पहले उन्होंने जिला प्रशिक्षण संस्थान में पांच महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने डाइट की वार्षिक पत्रिका नारकसाड का विमोचन भी किया।

राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकारों के कारण जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा मिला तथा इन क्षेत्रों के विकास कार्यो के लिए धन का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया।

मुख्यमंत्री ने बंगाणा को दी 119.51 करोड़ रुपये की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बंगाणा में तीन दिवसीय पिपलू मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने बंगाणा स्थानीय विश्राम गृह में

लोगों की समस्याएं सुनने के बाद शोभायात्रा में भाग लिया। भलेती में जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति व भाईचारे के प्रतीक होते हैं। उन्होंने बंगाणा के लोगों को मेले की बधाई दी।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने उपमंडल बंगाणा में लगभग 119.51 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यो के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने 2.12 करोड़ रुपये से निर्मित अधिशाषी अभियंता के संभागीय कार्यालय भवन थानाकलां, 61.51 लाख रुपये से बरनोह में निर्मित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रशिक्षण केंद्र, 2.44 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जठेहड़ी के स्कूल भवन, 1.45 करोड़ रुपये से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमियाड़ी, 93.69 लाख रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंदली में स्कूल के 4 कमरों, 10.31 करोड़ रुपये से ओलिंडा से बोहरू सम्पर्क मार्ग के मैटलिंग/टारिंग और 12.22 करोड़ रुपये से सैली से हंडोला वाया कमून पट्यिां और सैली महादेव मंदिर वाया जीपीएस लूबोवाल सड़क तथा 10.73 करोड़ रुपये से ग्रामीण आजीविका केंद्र बंगाणा के भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने 2.35 करोड़ रुपये से झंबर – कुरियाला – सुरजेहड़ा, मदनपुर – बसोली, पनोह – घंडावल और धमांदरी – संझोट उठाऊ जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, 10.59 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत मोह मीनार में बौल और मोह खास के लिए सिंचाई योजना, 1.83 करोड़ रुपये से टक्का और लोअर बसाल में टयूबवैल निर्माण, 7.20 करोड़ रुपये से सिंचाई सुविधा के लिए जस्साना खड्ड, बंगाणा खड्ड, थानाकलां और छपरोह खड्ड में वर्षा जल संग्रह संरचना के निर्माण, 6.72 करोड़ रुपये से राज्य कर और उत्पाद शुल्क केंद्रीय प्रवर्तन क्षेत्र ऊना कार्यालय के आवास के निर्माण कार्य, 5.98 करोड़ रुपये से खरूनी से खैरियां वाया चपलाह, गारली – डीहर, मकड़ी और चम्बोआ सड़क, 10.44 करोड़ रुपये से नाबार्ड के तहत बौल, झम्बर, लाम, टक्का और मौहल्ला बातियां हरिजन में पुल निर्माण कार्य तथा 33.59 करोड़ रुपये से भियांबी से बड़सर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा, एडवोकेट जनरल अनूप रतन, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. विजय डोगरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम आसरा, पार्टी पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एक अच्छे घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और एक अच्छे माता – पिता के बराबर कोई शिक्षक नहीं है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या कर्ज के सहारे प्रदेश बन पायेगा आत्मनिर्भर

क्या प्रदेश का संचालन कर्ज लिये बिना नहीं हो सकता यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि सुक्खू सरकार ने अपने पहले ही विधानसभा सत्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन एक्ट में संशोधन करके प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की सीमा बढ़ा दी थी। पहले यह नियम था कि राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पादन का तीन प्रतिशत तक ही कर्ज ले सकती है। सरकार बनने के बाद इस अधिनियम में संशोधन करके कर्ज की यह सीमा बढ़ा दी गयी थी। कर्ज की सीमा बढ़ाना वित्तीय कुप्रबन्धन का सीधा प्रमाण माना जाता है। केन्द्र प्रदेश का हक देने की बजाये कर्ज लेने के लिये प्रोत्साहित करता रहा है। आज कर्ज की किश्त चुकाने के लिये भी कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। जिस गति से यह कर्ज भार बड़ रहा है उससे यह लगता है कि इसी सरकार के कार्यकाल में यह कर्ज 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा। इस वित्तीय परिदृश्य में मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं 2030 में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का दावा कर रहे हैं। सरकार को बताना होगा कि उसका प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप क्या है?

सुक्खू सरकार अपने संसाधन बढ़ाने के बजाये टैक्स लगाने पर जोर दिया है, कर और शुल्क इस कदर बढ़ाये गये हैं कि समाज का हर वर्ग उससे प्रभावित हुआ है। अपने दो वर्ष के कार्यकाल में भारी कर प्रदेश की जनता पर लगा चुकी है। यह सब तब हुआ है जब सरकार ने दोनों वर्ष कर मुक्त बजट दिये हैं। हिमाचल बेरोजगारी में देश के पहले छः राज्यों में शामिल है इसलिये कांग्रेस ने प्रतिवर्ष एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी। लेकिन इस गारंटी पर काम करने से पहले ही उस संस्थान को भ्रष्टाचार के आरोपों की आड़ में भंग कर दिया जिसके जिम्मे रोजगार देने की प्रक्रिया संबंधी जिम्मेदारी थी।

प्रदेश में सरकारी बसों के किराये बढ़ा दिये हैं। अब हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम कराया 10 रु है। अब स्वास्थ्य जांच की पर्ची के भी प्रदेश में 10 रु लिये जायेंगे। अस्पतालों में कुछ टेस्ट निशुल्क होते थे उन पर शुल्क लगा दिया गया है। हिम केयर योजना भी प्रदेश सरकार नहीं चला पा रही है। आज सरकार के पास अपने चुनावी वायदे पूरे करने के लिए सेवाओं के दाम बढ़ाने और कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा नहीं है। आज हर चीज के दाम बढ़ने से लोगों में रोष पनपता जा रहा है जिस से सरकार की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि सरकार ने कर्ज का पैसा कहां खर्च किया? क्योंकि कर्ज लेकर दान नहीं दिया जाता है। इसी के साथ भ्रष्टाचार को बेनकाब करके दोषियों के खिलाफ कढ़ी कारवाही करनी होगी। अपने अनावश्यक खर्चो पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। जबकि सरकार लगातार व्यवस्था बदलने की दिशा में काम करने की बातें कर रही है लेकिन व्यवहारिक रूप से उसके प्रशासनिक फैसलों से इस तरह के कोई संकेत सामने नहीं आ रहे हैं। जिस वजह से आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेताओं तक कोई भी इस व्यवस्था परिवर्तन की व्याख्या कर पाने की स्थिति में नहीं है। आज जनता सरकार की हर चीज पर नजर रख रही है। कर्ज लेना विकास का कोई मानक नहीं है। बल्कि कर्ज लेकर घी पीने का पर्याय बन चुका है।

कबीर के चिंतन की समाजवादी मिमांसा

गौतम चौधरी

हद हद टपे सो आलिया,
अनहद टपे सो पीर,
हद – अनहद दोनों टपे,
बको नाम कबीर।

उक्त बातें कबीर दास के बारे में कबीर दास जी ने खुद कहा है। इसका अर्थ यह है कबीर हद और अनहद दोनों को साध चुके थे। इसलिए मध्यकालीन भारत में जितना ज्यादा आम लोगों पर कबीर ने प्रभाव छोड़ा, उतना किसी ने नहीं छोड़ा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कई कवियों का नाम आता है लेकिन कबीर दास ऐसे कवि थे जिन्होंने आम लोगों के मन की बात की। कबीर दास को आधुनिक भारतीय समाजवाद का प्रणेता कहा जाना चाहिए। उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिपेक्ष में परिभाषित किया और लोगों के सामने परोस। उस समय के ताकतवर समाज जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में दबदबा था, उसको उन्होंने चुनौती दी। उनके जड़वादी चिंतन पर कबीर दास ने जबरदस्त प्रहार किया। अपनी रचना में वे कहते हैं, ''जे बाभन बभिनिया जय, आन द्वार कहे नहीं आया।'' इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन ब्राह्मणवाद का प्रतिकार किया। कबीर दास एक ऐसे संत और कवि थे जिन्होंने एक खास प्रकार के सामाजिक आदेशों का उन्मूलन करते रहे। यही नहीं इस्लामी जड़वाद पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं, कांकड़ – पत्थर चुन के मस्जिद दियो बनाए, ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा भायो खुदाय। ''इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा, मंदिर तथा मस्जिद जैसे पारवंड का प्रभावशाली तरीके से प्रतिकार किया है। कबीर कहते हैं, ''पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पुजूं पहाड़, ता से तो चक्की भली, पीस खाए संसार।''

इस प्रकार हम देखते हैं, कबीर दास की रचनाओं में केवल भक्ति ही नहीं है, केवल भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, केवल सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन की बात ही नहीं कही गई है अपितु कबीर अपनी रचनाओं में धार्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात करते हैं। कबीर यह कहते हैं कि भगवान के यहां से जो भी आया है वह सब एक समान है। यही नहीं कबीर दास तो केवल मानव और मानव के बीच के संबंधों की व्याख्या ही नहीं करते हैं, उनके मन में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम दिखता है। कबीर दास दुनिया के तमाम जीव को एक ही भाव से देखते हैं और कहते हैं कि दुनिया में जो भी आया है, जिसको भी भगवान के द्वारा रचा गया है, उसका आपस में अंतर संबंध है। वह एक ही पिता का पुत्र है और एक ही आत्मा का विस्तार है।

आज हम जिस राजनीतिक समाजवाद की बात करते हैं उसमें केवल मानवों के बीच आपसी समानता की बात कही गयी है लेकिन कबीर तो जीव – जंतु, वृक्ष – पौधे, यहां तक की निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और कहते हैं की पूजा तो उसकी होनी चाहिए जिससे मानव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित हो रहा है। मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई है, जो केवल पत्थर की मूर्ति है और उसमें काल्पनिक प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है, ऐसे मूर्तियों की पूजा करने से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला है और यह एक भ्रम है। इस भ्रम से आडंबर पैदा होता है और यह धर्म, संस्कृति मानवता के खिलाफ है। अंर्तगत्व इससे मानव जाति को हानि ही पहुंचने वाली है किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार कबीर दास ऐसे समाजवाद की बात करते हैं जो दुनिया को संपूर्णता मैं देखता है और संपूर्ण कायनातों को एक मानता है। इसलिए कबीर को भारतीय आधुनिक समाजवाद का प्रणेता माना जाना चाहिए।

आजकल के समाजवादी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगे हैं और यह मानकर चलते हैं कि मानव के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बेहद जरूरी है। लेकिन कबीर दास जी आज से सैकड़ो साल पहले यह कह गए कि मानव तभी जिंदा रहेगा जब उसके चारों तरफ का वातावरण उसके अनुकूल रहेगा। जीव हत्या, हिंसा और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ कबीर दास जी ने एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया। हालांकि कालांतर में उनका सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन कई विकृतियों का शिकार हुआ लेकिन उन्होंने अपने समय ऐसे ऐसे प्रयोग स्थापित किए जो परंपराओं को चुनौती तो नहीं दे रहा था लेकिन मानवीय मूल्यों को और ज्यादा बेहतर तथा मजबूत बनाने में सफल रहा।

समाजवाद के प्रणेता के रूप में राबर्ट ऑवेन और सेंट साइमन का नाम पहले स्थान पर आता है। इन दोनों चिंतकों ने यह देखा कि जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, लोगों में समृद्धि नहीं आएगी और संसाधन का सही तरीके से बटवारा नहीं होगा, तब तक मानवीय समाज का विकास संभव नहीं है। उसी की अगली करी में कार्ल मार्क्स आए और सेंड साइमन तथा राबर्ट ऑवेन के समाजवाद को उन्होंने वैज्ञानिक कसौटी पर कस दिया। इसलिए मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स ने विज्ञान के आधार पर समाजवाद को परिभाषित किया। मार्क्स ने कहा की दुनिया संघर्षो का इतिहास है। मार्क्स का यह चिंतन है की संघर्षो के आधार पर ही दुनिया में परिवर्तन हुआ है और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। यहां पर मैं मार्क्स और कबीर के चिंतन तुलना नहीं कर रहा लेकिन इतना तो तय है कि जहां मार्क्स एक ओर संघर्षो के इतिहास और संघर्षो के द्वारा विकास की बात करते हैं, वही कबीर दास मानवीय मूल्यों में परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं समन्वय की बात करते हैं। इसलिए मार्क्स के चिंतन से कबीर का चिंतन थोड़ा भिन्न है। दोनों चिंतक सामाजिक समानता और सभ्यता के विकास की बात कर रहे हैं लेकिन दोनों चिंतकों के प्रक्रिया तथा कार्य पद्धति में भिन्नता है। जहां वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स विकास की पृष्ठभूमि में संघर्ष को देखते हैं, वही कबीर दास विकास के लिए समन्वय प्रभावशाली हथियार के रूप में चित्रित करते हैं।

इस प्रकार समाजवाद दोनों जगह है। मार्क्स एक ऐसे समाजवादी हैं जिन्होंने मानवीय समानता की बात की। उन्होंने संसाधन और उत्पादन में समान हिस्सेदारी की बात किया है, जबकि कबीर दास, मार्क्स से कई कदम आगे बढ़कर चिंतन करते हुए कहा है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है लेकिन उस परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वह सामाजिक और धार्मिक सामान्य की है। अगर धार्मिक, सामाजिक और संस्कृत सामान्य समाज में स्थापित हो जाए तो आर्थिक समानता की जरूरत ही नहीं पड़ती है। संसाधन में खुद व खुद समान हिस्सेदारी तय हो जाती है साथ ही शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती चली जाती है। इसलिए जहां एक ओर मार्क्स चिंतन भूकंपीय चिंतन है वहीं दूसरी ओर कबीर दास का चिंतन भूदोलन भूसंचलनात्मक है। कबीर दास के चिंतन और कार्य पद्धति से समाज में लंबे समय के बाद परिवर्तन दिखेगा या आ सकता है लेकिन वह परिवर्तन बेहद अस्थाई और प्रभावशाली होगा।

यहां एक बात और बता देना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स या पश्चिमी सोच वाले जो समाजवादी है, उन्होंने केवल मानव केंद्रित समाजवाद की बात की है लेकिन कबीर दास संपूर्णता में समाजवाद की बात करते हैं। उनके लिए प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भोग और उपभोग की प्रक्रिया में कबीर दास त्याग की बात करते हैं। वस्तुओं की उपयोगिता पर बल देते हैं और चक्रीय परिवर्तन व चक्रीय विकास की बात करते हैं। लेकिन पश्चिमी समाजवादी चिंतन ऐसा नहीं कहता है। वहां उपभोग और भोग को त्याग की कसौटी पर नहीं कसा गया है। इसलिए यदि ऐसा कहा जाए कि भारत के समाजवाद का प्रयोग पुराना है साथ ही वह परंपराओं से मुठभेड़ करने वाला नहीं है तो बेहतर होगा। यह एक समन्वय का, संतुलन का और समानता का समाजवाद है, जबकि पश्चिम का समाजवाद केवल और केवल मानव केंद्रित है और प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करने वाला है जबकि भारत के खास करके कबीर दास का जो समाजवाद है संपूर्ण प्रकृति की चिंता करने वाला तथा समन्वयवादी समाजवाद है।

सरकार ने डेयरी सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत

शिमला। हिमाचल प्रदेश ने देश में पहली बार दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रदेश के पशुपालकों से प्रतिदिन 2.32 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। वहीं सहकारी संस्थाओं को छह करोड़ रुपये वार्षिक सहायता देकर सरकार ने न केवल किसानों की आय में वृद्धि की है बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण और समृद्धि की एक

नई मिसाल कायम की है। यह पहल राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता और सतत् प्रगति का प्रतीक है। पिछले अढ़ाई वर्षों में सरकार ने दूध उत्पादकों को सशद्ध बनाने और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने तथा ग्रामीण अर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की है।

वर्तमान में सरकार लगभग 38,400 पशुपालकों से रोजाना औसतन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध खरीद रही है, जिसे गुणवत्ता के आधार पर 51 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 1,482 भैंस पालकों से प्रतिदिन 7,800 लीटर दूध खरीदा जा रहा है, जिसे 61 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। ये दाम पशुपालकों को स्थिर और सुनिश्चित आय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

राज्य सरकार दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में दूध आपूर्ति की चुनौती को देखते हुए पशु पालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का परिवहन भत्ता प्रदान कर रही है। इससे छोटे और सीमान्त किसानों को बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो रही है और उनकी परिवहन लागत में कमी आई है।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हिम गंगा' ग्रामीण स्तर पर डेयरी उत्पादन में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के अंतर्गत हमीरपुर और कांगड़ा जिला में 268 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई है, इनमें से हमीरपुर में 11 और कांगड़ा में 99 समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। हमीरपुर की 46 समितियों में से 20 महिला समितियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। कांगड़ा जिला में कुल 222 सहकारी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे 5,166 किसान जुड़कर संगठित तौर पर दुग्ध उत्पादन और बिक्री सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने बकरी दूध खरीद के लिए भी एक पॉयलट परियोजना आरम्भ की है जिसके तहत बकरी पालकों से प्रतिदिन लगभग 100 लीटर दूध 70 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इस योजना से वर्तमान में 15 बकरी पालक लाभान्वित हो रहे हैं।

दूध सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन भत्ते को 1.50 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह प्रावधान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 और हिमाचल प्रदेश कॉ-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1968 के अंतर्गत पंजीकृत सभी समितियों पर लागू है। इस योजना पर सालाना लगभग छह करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है, जो भविष्य में समितियों की संख्या बढ़ने के साथ और बढ़ा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए दुग्ध सुधार केवल उत्पादकों के आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। यह प्रदेश को एक ऐसा स्थायी और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की दिशा में प्रयास है जिससे किसानों की आय में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यात्रा में दुग्ध क्षेत्र एक प्रेरक मिसाल है, जिसके माध्यम से राज्य एक ऐसा मॉडल विकसित करेगा जो अन्य राज्य के लिए उदाहरण होगा।

रक्षा राज्य मंत्री ने शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा किया

शिमला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 09 जून, 2025 को हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण

कमान (एआरटीआरएसी) का दौरा किया। उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एआरटीआरएसी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा द्वारा देश भर में फैले 34 प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के माध्यम से संस्थागत प्रशिक्षण के रूप में कमान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय सेना के सामने आने वाली समकालीन व भविष्य की चुनौतियों के आधार पर सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के निर्माण के साथ-साथ सैन्य नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं में आगे की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

रक्षा राज्य मंत्री ने रणनीतिक सेना प्रमुखों को सशक्त बनाने, ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी अवशोषण और कार्यात्मक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के संबंध में एआरटीआरएसी की पहल की सराहना की। उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन के एक हिस्से के रूप में विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सेना को एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी संचालित, आत्मनिर्भर और युद्धक परिस्थितियों के लिए तैयार सैन्य बल में रूपांतरित करने में कमान की भूमिका की सराहना की।

संजय सेठ ने एआरटीआरएसी मुख्यालय में कार्मिकों के साथ बातचीत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त समन्वय का उल्लेख किया। उन्होंने सेना प्रशिक्षण कमान की सराहना की और इसे आतंकवाद तथा इसके अपराधियों के खिलाफ लड़ने में भारत के दृढ़ रुख का सफल प्रदर्शन बताया। रक्षा राज्य मंत्री ने एनसीसी और सैनिक स्कूलों के विस्तार हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

रक्षा राज्य मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आर्मी हेरिटेज म्यूजियम परिसर में एक पौधा भी लगाया।

हिम इरा शॉप से आत्मनिर्भरता और संस्कृति का नया अध्याय

मंडी जिले की चुराग विकास खंड की ग्राम पंचायत सवा माहू के अंतर्गत दानवीर कर्ण श्री मूल माहूंनाग मंदिर के श्री चरणों में गाँव की महिलाओं द्वारा दो वर्ष पूर्व शुरू हिम इरा शॉप आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। जहां कभी वे केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वहीं इस शॉप के माध्यम से 100 से अधिक महिलाएं पारंपरिक शिल्प और उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाकर सालाना एक निश्चित आय अर्जित कर रही हैं।

मंदिर के कदमों तले व्यापार

माहूंनाग मंदिर के ठीक पास स्थित इस शॉप में 20 विभिन्न उत्पादन बांस की टोकरियाँ, ऊनी जैकेट, देशी घी, हल्दी, राजमाह, मोटे अनाज के बीज, हाथ से बनी सजावटी वस्तुएं, आचार मसाले आदि उपलब्ध हैं। प्रतिमाह यहाँ 25.30 हजार रुपये का कारोबार होता है, जिससे पूरे समूह की सामूहिक आमदनी बढ़कर दो लाख रुपये के करीब पहुंच चुकी है।

संस्कृति का साक्षात् संगम

हिम इरा शॉप सिर्फ खरीदॉ फरोख्त का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति का जीवंत मंच बन चुका है। हर सजीव कला उत्पाद के साथ पर्यटक गाँव की लोककहानियों, रीति रिवाजों और हस्तशिल्प के पारंपरिक ज्ञान से रूबरू होते हैं, जो आने वाले पीढ़ी के लिए संरक्षण का काम करता है।

डिजिटल विश्व में कदम

आने वाले समय में हिम इरा समूह ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी जुड़ने के प्रयास कर रहा है। जिसके लिए समूह की महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग इत्यादि का वर्कशॉप के माध्यम से प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है, ताकि हिम इरा उत्पाद प्रदेश की सीमाओं से परे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक भी पहुँच सकें।

भविष्य की योजना

समूह की प्रधान का कहना है कि समूह भविष्य की योजना पर भी कार्य कर रहा हैं। महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उत्पादों को एकरूप लेबल और आकर्षक पैकेटिंग देना हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन विस्तार, ई. कॉमर्स पोर्टल पर स्टोर खोलना, सोशल मीडिया प्रचार और गाँव में ही कारीगरों को नई तकनीक, डिज़ाइन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की ट्रेनिंग देने आदि की योजना

पर भी समूह कार्य कर रहा हैं।

बाहरी राज्यों से आकर्षण

पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बंगाल से आने वाले श्रद्धालु यहाँ के ऊनी जैकेट और हस्तनिर्मित उत्पादों को विशेष रूप से महत्व देते हैं।

जिससे पता चलता है कि ग्रामीण शिल्प को सही मंच और गुणवत्ता मिले तो बड़े बाजारों में भी जमकर प्रतिस्पर्धा की जा सकती है।

पवना ठाकुर सदस्य,स्वयं सहायता समूह

पहले हम घर की दहलीज भी नहीं पार करती थीं, आज खुद अपना उत्पाद बेचते हैं और स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं। इससे हमें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खोले हैं।

त्वारकू देवी, प्रधान, गंगा स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन का कहना है कि प्रारंभ में हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी मेहनत सफल होगी, लेकिन दानवीर कर्ण श्री मूल माहूंनाग के आशीर्वाद और कृपा दृष्टि से हम सभी महिलाएं सफल हो रही हैं। अब हम 'हिम इरा' नाम को ब्रांड बनाकर देशभर में पहुंचाना चाहती हैं। जिसके लिए प्रयास किए जा रहे है।

हिम इरा शॉप न सिर्फ एक व्यावसायिक पहल है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर भी है। यह मॉडल देशभर के अन्य ग्रामीण समुदायों के लिए प्रेरणा बनकर उभरेगा, जहाँ गांव की बेटियां और महिलाएं अपनी मेहनत व हुनर से आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन दोनों पा रही हैं।

चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत रुझान साझाकरण प्रक्रिया को उन्नत करेगा

शिमला। चुनाव आयोग अब अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझानों को अद्यतन करने के लिए सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू कर रहा है। यह नई प्रक्रिया पहले की मैन्युअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करती है। यह पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर इसकी आवश्यकता को रेखांकित करते रहे हैं।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस के वैधानिक ढांचे के तहत, पीठासीन अधिकारियों (पीआरओ) को दर्ज किए गए मतों का विवरण देने वाला फॉर्म 17सी, उम्मीदवारों द्वारा नामित मतदान एजेंट (जो मतदान का समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं) को देना अनिवार्य है। इस कानूनी आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतदान प्रतिशत रुझान की वीटीआर ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेजी से अपडेट करने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है। यह ऐप जनता को अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझानों से अवगत कराने के लिए एक सुविधाजनक, गैर-वैधानिक तंत्र के रूप में विकसित की गई थी।

इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (पीआरओ) अब मतदान के दिन प्रत्येक दो घंटे में नए ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाताओं की उपस्थिति दर्ज करेंगे ताकि अनुमानित मतदान रुझानों के अद्यतन में समय अंतराल को कम किया जा सके। इसे स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझान पहले की तरह प्रत्येक दो घंटे में अपडेट होते रहेंगे। विशेष रूप से, मतदाता उपस्थिति डेटा अब मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी में दर्ज किया जाएगा, जिससे देरी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के अधीन मतदान समाप्त होने के बाद अद्यतन किए गए वीटीआर ऐप पर निर्वाचन क्षेत्रवार डाले गए मतों का अनुमानित प्रतिशत उपलब्ध होगा। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद प्रविष्टियां ऑफ़लाइन की जा सकती हैं और अपडेट की जा सकती है।

इससे पहले, सेक्टर अधिकारियों द्वारा हाथ से लिखे हुए रूप में मतदान डेटा एकत्र किया जाता था और फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को रिले किया जाता था। यह जानकारी प्रत्येक दो घंटे में एकत्र की जाती थी और वोटर टर्नआउट (वीटीआर) ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट किए जाते थे, जो देर रात या अगले दिन आने वाले लिखित रिकॉर्ड पर आधारित होते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इस कारण कुछ लोगों में गलतफहमियां पैदा होती थीं।

मुख्यमंत्री ने 89 पौंगडैम विस्थापितों को भूमि के कागज़ात प्रदान किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में कार्यक्रम के दौरान 89 पौंगडैम स्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष स्थानीय विधायक ने पौंगडैम विस्थापितों के मामले की पुरजोर वकालत की। यह परिवार गत 50 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का पिछले 25 वर्षों तक कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। अहंकार के भाव में आकर एक निर्दलीय विधायक ने लोकतंत्र का अपमान करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और 11 माह पहले उप-चुनाव में जीत दर्ज कर कमलेश ठाकुर को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में देहरा क्षेत्र कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। देहरा के दौरे के दौरान नंदपुर की दो लड़कियों ने मुझे अवगत करवाया कि बरसात के मौसम के दौरान यहां आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। अब मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष दिसम्बर तक नंदपुर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्व में यह कहावत प्रचलित थी कि देहरा का कोई नहीं लेकिन अब मैं कहता हूं कि देहरा मेरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान निर्मित किया

जा रहा है और अगले वर्ष तक इसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से देहरा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए पंख लगेंगे और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है और प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वन्य जीव विंग कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित किया है। आगामी समय में और सरकारी कार्यालय कांगड़ा जिले में स्थानान्तरित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय रूप से काफी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी से राज्य को वार्षिक 3000 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे लेकिन अब प्रदेश को केवल 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

इस अवसर पर देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छह माह के भीतर क्षेत्र के विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि देहरा में पर्यटन परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान भी शामिल हैं, जिसके दो प्रभागों की मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि रानीताल से मुबारकपुर सड़क परियोजना को स्वीकृति दी गई है और देहरा के पीडब्ल्यूडी सेक्टर में 214 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2023 में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 24 पेयजल योजनाओं की बहाली पर 43 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें जल शोधन संयंत्र की स्थापना भी शामिल हैं।

पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री की सराहना करे हुए कहा कि वह जमीनी स्तर से राजनीति आरम्भ करके आज प्रदेश के शीर्ष मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देहरा के साथ-साथ पूरा प्रदेश उन्नति कर रहा है।

पुरानी पेंशन योजना से पीछे हटने वाली नहीं राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में आयोजित दो दिवसीय 32वीं हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के समापन कार्यक्रम के दौरान साइंस

क्विज, मैथेमेटिकल ओलंपियाड, इनोवेटिव साइंस मॉडल, साइंस स्किल, निबंध लेखन तथा स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में 12 जिलों से आए लगभग 600 बाल वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रसार के लिए दो करोड़ की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती थी, लेकिन अब वह राशि बंद हो गई है। हिमकोस्टे के आग्रह पर मैंने धन उपलब्ध करवाया। अब बच्चों में वह आत्मविश्वास नजर आ रहा है, जिससे वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। यह एक सोच है जो हिमाचल प्रदेश के बच्चों में देखने को मिल रही है और अध्यापक ही इस सोच को विकसित करते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को बचाना आवश्यक है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और हम इस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 350 ई-बसें शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले समय में निगम का पूरा बेड़ा ई-व्हीकल में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन है और हिमाचल प्रदेश पूरे देश को इस दिशा में रास्ता दिखाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास कर रही है और अगले वर्ष तक हम 100 सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने जा रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जिनमें से कई स्कूल अगले साल तक शुरू कर दिए जाएंगे। हम आने वाले समय में 967 टीजीटी तथा पीजीटी अध्यापकों की भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा जेबीटी में भी एक हजार पद भरे जाएंगें ताकि अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार बार-बार यूपीएस लागू करने को कह रही है लेकिन राज्य सरकार ओपीएस से पीछे हटने वाली नहीं है।

सदस्य सचिव डीसी राणा ने हिमकोस्टे की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आठ व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार समारोह शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित किया गया। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के लिए 50-50 हजार रुपये जबकि तृतीय पुरस्कार के लिए 25 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की गई।

शैक्षणिक संस्थान श्रेणी में राजकीय

और मेसर्स ल्यूमनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अंब जिला ऊना को दिया गया।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंगेर, जिला ऊना के रुव को पहला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर, चंबा की आरुही को दूसरा स्थान और एचएपीएस, हीरा नगर, हमीरपुर की नामी को तीसरा प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। वरिष्ठ वर्ग में राजकीय उच्च विद्यालय नवबहार, शिमला की रोशनी को पहला स्थान, सेंट ल्यूक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोलन की महक प्रीत को दूसरा स्थान और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पांगी, किन्नौर के आयुष नेगी को तीसरा स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

नारा लेखन प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में राजकीय उच्च विद्यालय कनाह, जिला सोलन की हर्षिता ने पहला स्थान, राजकीय उच्च पाठशाला भीतलू, कांगड़ा की सूनाक्षी ने दूसरा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारंग, किन्नौर की दिव्या सोलन ने दूसरा तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवीं बिलासपुर को तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जिंदल विद्या मंदिर, शोल्टू, किन्नौर के अभिनव ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सौर जिला सोलन विकास ने द्वितीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुटी शिमला की इक्षिता ने तृतीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थरास जिला कुल्लू की साक्षी ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।

वाद-विवाद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ विद्यालय कोटला सोलन की इशिता ने पहला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घणाहट्टी शिमला की कोमल मेहता ने दूसरा, नूरपुर पब्लिक स्कूल नूरपुर कांगड़ा की आराधना ठाकुर ने तीसरा तथा टी.आर.डी.ए.वी स्कूल कांगू हमीरपुर की अंशिका शर्मा चौथे स्थान पर रही।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा चालाए जा रहे हरित स्कूल कार्यक्रम के तहत भी कई पुरस्कार प्रदान किए गए। जिला सोलन ने श्रेष्ठ ग्रीन जिला पुरस्कार प्रदान किया जबकि राजकीय उच्च विद्यालय कनाह सोलन को भूमि प्रबंधक पुरस्कार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिमला जिले के बलदेयां को परिवर्तन निर्माता विद्यालय, दून वैली पब्लिक स्कूल सोलन को ऊर्जा प्रबंधक पुरस्कार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलेठ जिला हमीरपुर को अपशिष्ट योद्धा पुरस्कार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरोग जिला शिमला को सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार और शिवालिक वैली पब्लिक स्कूल सोलन को जल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए।

इन पुरस्कारों के माध्यम से विजेताओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में किए गए अनुकरणीय प्रयासों को सराहा गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'प्लास्टिक चैलेंजिंग मोबाइल ऐप' को भी लॉन्च किया। यह ऐप पर्यावरण कानूनों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस ऐप के माध्यम से 13 विभागों के अधिकारी अब मोबाइल के माध्यम से सीधे चालान कर सकेंगे, जिससे कागज आधारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पात्र महिला मतदाताओं का करवाया गया पंजीकरण

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात प्रदेश का महिला मतदाता लिंग अनुपात 981 है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर का महिला लिंग अनुपात 921 है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 59-शिलाई का महिला लिंग अनुपात 821 है जो कि कम महिला मतदाता लिंग अनुपात के लिए चिन्हित 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे कम है।

उन्होंने बताया कि महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायत सचिव द्वारा तैयार किए गए परिवार रजिस्टर के साथ मतदाता सूची का त्रैमासिक आधार पर मिलान करके मतदाता सूची में शामिल नहीं की गई पात्र महिला मतदाताओं की सूची संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को दें ताकि वे मतदाताओं का पंजीकरण कर सकें। यह प्रक्रिया जिला सिरमौर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 59-शिलाई में आरम्भ की जा रही है, जिसमें परिवार रजिस्टर के साथ मतदाता सूची का मिलान का कार्य जून महीने में किया जायेगा तथा पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई मास में पूर्ण कर ली जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 04 व 05 जून, 2025 को 59-शिलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालीकोटी, बांदली और कांडो-भटनोल में स्थानीय महिलाओं के साथ संवाद कर मौके पर उपस्थित बूथ स्तर अधिकारी के माध्यम से पात्र महिला मतदाताओं के फार्म भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी पूर्ण करवाई।

उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार करके इस विशेष अभियान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करने के भी निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी शिलाई डॉ. अभिषेक ठाकुर तथा उपमंडलाधिकारी कफोटा निशा आजाद भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने गगरेट विस में किए 75.10 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना ज़िला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 75.10 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिनमें 42.82 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 3 के तहत स्वां नदी पर अंब – अम्बोटा मार्ग पर 400 मीटर स्पेन पुल का निर्माण, 2.70 करोड़ रुपये से पीएमजीएसवाई – 3 के तहत गगरेट से ओयल वाया सीरियां – उपरली सम्पर्क मार्ग टी – 04 पर टाटचरा खड्ड, मवा – सिधियां खड्ड, शिलांग खड्ड व लोहारली खड्ड पर 4 पुल, 3.59 करोड़ रुपये से पिपलू से लोहारली – उपरली सम्पर्क मार्ग टी – 05 में जाडला खड पर पुल के निर्माण, 6. 46 करोड़ रुपये से राम मंदिर से बने – दी – हट्टी वाया अंदोर अपरला, जट्टां – दा – बेहड़ा – अठवां सड़क पर मेटलिंग – टारिंग के निर्माण तथा 2.79 करोड़ रुपये से राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक के भवन निर्माण के शिलान्यास शामिल हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 2. 27 करोड़ से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा में वर्कशॉप, 1.85 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना शिवपुर व बने – दी – हट्टी, 1.03 करोड़ रुपये से गोंदपुर – बनेहड़ा कम्पोजिट उठाऊ पेयजल योजना, 1.08 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत शिववाड़ी में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 3.10 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत नकड़ोह में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 2.40 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत अमलैहड़ और भंजाल में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 1.05 करोड़ रुपये से अप्पर अंदौरा, 1.02 करोड़ रुपये से

अंदौरा – एक, 1.05 करोड़ रुपये से मवा सिंधियां और 1.07 करोड़ रुपये से नकड़ोह में टयूबवैल के सुधारीकरण और 82.18 लाख रुपये से कैलाश नगर में टयूबवैल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण भी किए।

उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र में ही 170 करोड़ रुपये की पानी की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का स्थाई समाधान होगा। उन्होने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जल योजनाओं के लिए होने वाले धन आवंटन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश को जारी होने वाले 2,000 करोड़ रुपये की बजाय अब तक केवल 137 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं। इससे इन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो रही है तथा लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने हक़ की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है।

स्थानीय विधायक राकेश कालिया ने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकासपरक मांगें रखीं। उन्होंने गगरेट अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल भवन के शेष कार्यों के लिए और धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने लोहारली और मुबारकपुर में 33 केवी स्टेशन कोलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाने का आग्रह किया।

विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के लिए वित्तीय सहायता तथा शिवबाड़ी मेले को ज़िला स्तरीय दर्जा देने की मांग रखी।

मुख्यमंत्री ने देहरा में 233.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 233.55 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मंगलवार को उन्होंने देहरा क्षेत्र के लोगों को 100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं भी समर्पित की थीं।

मुख्यमंत्री ने देहरा में जलशक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन को भी समर्पित किया, जिससे लगभग पांच लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में 7. 26 करोड़ रुपये से निर्मित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत बाड़ा में सुनहेत – बस्सी सड़क पर नारद खड्ड पर 1.75 करोड़ रुपये से बने पुल का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने देहरा बाईपास पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 10 लाख रुपये की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं तथा राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देहरा में 38 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, देहरा में 99 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन, 4.73 करोड़ रुपये की लागत से वन विश्राम गृह, देहरा, सुनहेत से बस्सी सड़क पर देही खड्ड पर 4. 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल, सुनहेत से बस्सी सड़क पर ढलियारा खड्ड पर 8.77 करोड़ रुपये की लागत से पुल, देहरा क्षेत्र में यूवी और गैसीय क्लोरीनेशन के साथ 43 करोड़ रुपये की लागत से 24 जलापूर्ति योजनाओं के जल उपचार संयंत्र का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रन को झंडी दिखाकर किया रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर, शिमला से 'प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना' ध्येय से आयोजित साइकिल रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम संयुक्त तौर पर पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल.2030 जागरूकता अभियान और स्वच्छ शिमला अभियान का भी शुभारम्भ किया।

इस अभियान में विद्यार्थियों, स्वयं सेवियों, गृह रक्षा जवानों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक न्यूट्रल बनाने की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पर्यावरण को प्लास्टिक से बचाना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के साथ – साथ जागरूकता लाने के लिए गंभीर प्रयासों की भी नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य से अलग पहचान है। इसे सदैव बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रयास करने होंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर फोरलेन कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया

शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भूभुजोत सुरंग सहित घटासनी – शिल्हा – बधानी – भूभुजोत – कुल्लू सड़क के सामरिक महत्व के दृष्टिगत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग रक्षा संबंधी सामग्री की सुचारू आवाजाही के लिए बेहतर मार्ग साबित होगा और इससे यात्रा की दूरी 55 किलोमीटर कम होगी।

लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर तक एनएच – 05 के फोरलेन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने वर्तमान में राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रधानमंत्री गति शक्ति में शामिल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।

विक्रमादित्य सिंह ने सीआरएफ के तहत 130 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने और राज्य में सीआरएफ कार्यों की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का भी अनुरोध किया।

नितिन गडकरी ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ढली – रामपुर फोरलेन प्रक्रिया को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता सुरेन्द्र पाल जगोता भी उपस्थित थे।

निर्वाचन आयोग वीटीआर साझा करने की प्रक्रिया को करेगा अपग्रेड

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू करेगा। यह नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करगी। मतदाता उपस्थिति वीटीआर ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया, पहले एक सहायक, गैर – वैधानिक तंत्र के रूप में विकसित की गई थी ताकि जनता को अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझानों से अवगत करवाया जा सके, अब इसे तेज़ और सटीक अपडेट सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने दी। यह पहल आयोग की समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई अवसरों पर रेखांकित किया है।

उन्होंने बताया कि इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी पीआरओ अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईएनइटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे मतदान रुझानों के अद्यतन में समय की देरी कम होगी।

उन्होंने कहा कि अब पीआरओ मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनइटी ऐप में आंकड़े दर्ज करेंगे, जिससे देरी कम होगी और मतदान समाप्ति के बाद अनुमानित मतदान प्रतिशत की जानकारी निर्वाचन क्षेत्रवार अद्यतन वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगी, बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।

उन्होंने बताया कि यह अद्यतन वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईएनइटी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। इससे पहले, मतदान डेटा सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किया जाता था और रिटर्निंग अधिकारियों को फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से भेजा जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्र कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी। कई बार मतदान प्रतिशत रुझनों को देर रात या अगले दिन भौतिक रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद ही अपडेट किया जाता था, जिससे 4 से 5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे शंका उत्पन्न होने की संभावना भी बनती थी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

उप-मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्री से अखिल भारतीय टैक्सी परमिट 15 वर्ष करने का आग्रह

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार रवैया अपनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य का विकास पूरी तरह से सड़कों और पुलों के विस्तार पर निर्भर करता है।

इस पहाड़ी राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रदेश के विकास के लिए सड़क और पुलों की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष परिवहन विभाग से संबंधित प्रमुख मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में ऑपरेटरों की मांग को राज्य सरकार ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वाहनों के संचालन की सीमा को 15 वर्ष किया गया है इसके दृष्टिगत अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को 15 वर्ष तक किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के अनुरोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मामले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को पूंजी निवेश (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) के लिए विशेष सहायता योजना के तहत शेष धनराशि 7.63 करोड़ रुपये शीर्ष जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।

उप-मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि नंगल से जैजों तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है। यह सड़क प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 429 करोड़ रुपये की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अमृतसर से होशियारपुर तक एनएच-503ए के प्रस्तावित फोर लेनिंग कार्य को बनखंडी (हिमाचल प्रदेश की सीमा) से झलेड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है और यह मार्ग श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी लाभ होगा। उन्होंने चंडीगढ़ से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन है।

उप-मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि सीआरआईएफ के तहत 48.69 करोड़ रुपये की लागत से जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई-का-मोड़ सम्पर्क मार्ग और 3 पुल को स्तरोन्नत करने को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

एक तरफ़ शुल्क बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ़ सुविधाएं छीन रही है सरकार:जयराम

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ़ सरकार हर दिन कोई न कोई शुल्क लगाये

जा रही है तो दूसरी तरफ़ प्रदेशवासियों को मिल रही सुविधाएं छीन रही है। महीनों से सरकार डिपुओं में सरसों का तेल और रिफाइंड नहीं दे रही थी। अब सरकार कह रही है कि डिपुओं में जो तेल और रिफाइंड मिलेगा वह 33 से 40 फीसदी महंगा होकर मिलेगा। जो रिफ़ाइडन तेल पहले लोगों 97 रुपए मिल रहा था अब लोगों को 134 रुपए में मिलेगा। यह प्रदेश के लोगों के साथ किसी मज़ाक से कम नहीं है। एक ही झटके में सरकार आम आदमियों के खान-पान से जुड़ी चीज़ें लगभग डेढ़ गुनी कैसे महंगी कर सकती हैं? ऐसा सिर्फ़ रिफाइंड-तेल के मामले में ही नहीं है। डिपुओं में मिलने वाली दालों समेत अन्य खाद्य वस्तुओं के मामले में भी सरकार ऐसा ही कर रही है। एक तरफ़ सरकार डिपुओं में मिलने वाले राशन की संख्या कम कर रही है तो दूसरी तरफ़ उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा कर रही है। क्या सरकार को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है? यह सरकार सुविधाएं देने के लिए है या सिर्फ़ और सिर्फ़ हर दिन शुल्क लगाने के लिए। सरकार इस तरह की मनमानी और जन विरोधी नीतियों से नहीं चलती है। मुख्यमंत्री को प्रदेशवासियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार का दावा करते-करते मुख्यमंत्री 'शुल्क की सरकार' के मुखिया बन गये हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री आये दिन प्रदेशवासियों पर किसी न किसी प्रकार का शुल्क लाद देते हैं और उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। वह अपने द्वारा थोपे गये शुल्क से साफ़ मुकर जाते हैं। बीते कल भी उन्होंने साफ़ कह दिया कि उन्होंने अस्पतालों की पर्ची पर कोई शुल्क नहीं लगाया है। तो अस्पतालों में शुल्क वसूला क्यों जा रहा है? लोग दस रुपए की पर्ची ख़रीद कर क्यों घंटों लाइन में खड़े हैं? एक दिन मुख्यमंत्री अस्पताल जाकर यह खुद चेक कर सकते हैं। क्या सरकार उनके अलावा भी कोई चला रहा है? इसी तरह से मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि चूड़धार यात्रा पर भी वन विभाग ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। जब उन्होंने लगाया नहीं है तो उनका विभाग वसूल कैसे रहा था। वह झूठ और कायदे से तब पकड़ा गया जब पिछले महीनें सरकार ने ही वह नोटिफिकेश वापस लिया गया कि अब चूड़धार यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री यह बताएं कि यदि शुल्क लिया नहीं जा रहा तो वापस क्या लिया गया? एक नहीं अनेकों ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्यमंत्री साफ़ झूठ बोल कर अपने कारनामें से मुकर जाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने में केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पीएमजीएसवाई के सभी चरणों में हिमाचल प्रदेश को प्रमुखता मिली है। चौथे चरण के तहत हिमाचल में डेढ़ हज़ार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्रों की तरह ही सराज विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 32 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह सराज के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि देश का अभूतपूर्व विकास ही 'मोदी की गारंटी' है। आज कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना पूरा हो गया। इस सपने को पूरा करने में कई रिकॉर्ड बने। कई ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जो आत्मनिर्भर और उत्कृष्ट भारत की क्षमताओं का शिलालेख है। जयराम ठाकुर ने चिनाब ब्रिज और भारत के पहले 'केबल-स्टेड अंजी' पुल के लोकार्पण के लिए समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चिनार ब्रिज कुतुब मीनार से पांच गुना एफिल टॉवर से यह 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है।